



Section. L.B.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 1 नवम्बर, 2004/9 आश्विन, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th September, 2004

No. EXN-F(3)-1/2001.—In exercise of powers conferred by section 56 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as applicable in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant the exemption in Excise Duty and Assessed Fee amounting to Rs. 3080/- Rupees Three thousand and Eighty only) on liquor to be used for celebrating Raising Day on 10th October, 2004 to 15th October, 2004 in favour of M/s Station Workshop EME, Jutogh, Shimla-8.

By order,

Sd/-  
Pr. Secretary.

यह कि उपमण्डलाधिकारी (ना०), गोहर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया गया जिसके फलस्वरूप यह पाया गया कि :—

1. आपने दिनांक 4-12-1998 को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जंजैहली से मु० 25,600/- रु० चैक संख्या 1483765 द्वारा निकाले जाते पुष्टि ग्राम पंचायत की वचत खाता पास बुक से होती है। उक्त चैक के अधपन्ना के अवलोकन से यह पाया गया कि अधपन्ना पर मु० 5000/- रुपये लिखे गये हैं तथा पंचायत रोकड़ के पृष्ठ 12 पर भी मु० 5000/- रुपये की निकासी दिखाई गई है। इस प्रकार आपने मु० 20,600/- रुपये का छलहरण किया जिससे आपके विरुद्ध धोखाधड़ी का आपराधिक मामला जनता है। उपरोक्त राशि के सन्दर्भ में आपका यह स्पष्टीकरण कि मु० 20,600/- रुपये की राशि के विरुद्ध मु० 27,540/- रुपये का व्यय मस्ट्रोल संख्या 482 अधि 10/98 निर्माण कार्य पर किया गया, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी सराज स्थित जंजैहली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त संख्या का मस्ट्रोल ग्राम पंचायत तुंगाधार को जारी नहीं किया गया दलिक मस्ट्रोल संख्या 482, विकास खण्ड द्वारा ग्राम पंचायत छतरी को जारी किया गया था। अतः उक्त मस्ट्रोल संदेहजनक पाया गया। इसके अतिरिक्त न तो उक्त राशि से किये गये निर्माण कार्य/कार्यों का निवरण और न ही इसके कोई वाउचर पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध हैं। इस प्रकार आपने धोखाधड़ी से मु० 20,600/- रुपये की धनराशि का छलहरण किया।

2. पास मई, 1997 के मस्ट्रोल, जोकि दिनांक 16-7-1997 को रोकड़ बही के पृष्ठ 77 पर दर्ज हैं, के अनुसार श्री नेव सिंह को दिनांक 3-5-1997 से, मजदूर क्रमांक 15 पर, काम पर दर्शाया गया है जबकि दूसरे मजदूरों, जो क्रम संख्या 16 से 19 पर दर्ज हैं, को दिनांक 1-5-1997 से काम पर दर्शा कर आपके द्वारा मु० 1317.60 की धनराशि का छलहरण पाया गया। इसी प्रकार मास 12/90 के मस्ट्रोल, जिसका वाउचर संख्या 93 है, से पाया गया कि क्रम संख्या 15 पर दर्शाये गये मजदूर को दिनांक 19-12-1999 से, क्रम संख्या 16 पर दर्शाये गये मजदूर को दिनांक 18-12-1999 से तथा क्रम संख्या 18 से 20 पर दर्शाये गये मजदूर को दिनांक 17-12-1999 से हाजर दर्शा कर आपने मु० 357/- रुपये का छलहरण किया है।

3. आपने अधि 4/2001 से 3/2002 के मध्य पंचायत निधि की विभिन्न राशियों को अपने पास अनावश्यक रूप से रोके रखा। आपने न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया है अपितु स्वेच्छापूर्वक सरकारी राशि का छलहरण भी किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त उप-निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा मई, 2004 को की गई जांच के फलस्वरूप निम्न अतिरिक्त तथ्य उजागर हुये हैं :—

1. आप द्वारा ग्राम पंचायत तुंगाधार का अधि 1-1-1997 से 1-10-2001 के बीच प्रधान पद पर रहते हुये बिना प्रस्ताव पारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सी० डी० बैंक जंजैहली से मु० 3,82,797/- रुपये की धनराशि अनाधिकृत रूप से जाली प्रस्ताव लिख कर निकाली गई।

2. यह कि आपके पति श्री चमन लाल द्वारा मुदलिक 50,000/- रु० की धनराशि चैक संख्या 1483775, दिनांक 28-4-1999 द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक शाखा जंजैहली से निकाली गई है। जबकि निकासी के लिये केवल आपको ही प्राधिकृत किया गया था। सरकारी धनराशि निकासी के लिये अनाधिकृत व्यक्ति से राशि बैंक से निकासी करवा कर आपने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 99 (4) तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया।

इसके अतिरिक्त उप-निदेशक, पंचायती राज विभाग ने सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर के साथ मौके पर कुछ विकास कार्यों का निरीक्षण किया जिसका व्यौरा निम्नलिखित है :—

### 1. निर्माण राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बेखली :

राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बेखली का निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया। मन्त्रि, ग्राम पंचायत तुंगाधार के अनुसार सरकारी धनराशि की कमी के कारण बन्द किया जाना बताया गया। सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर की रिपोर्ट अनुसार अब तक किये गये निर्माण कार्य का मूल्यांकन मु० 85,000/- रु० है। जबकि पंचायत रिकार्ड के अनुसार मास 4/2001 तक मु० 95,190.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा मु० 10,190/- रु० का दुरुपयोग किया जाना पाया गया।

### 2. निर्माण बावड़ी दांवन्त :

यह कि दांवन्त नामक स्थान में बावड़ी निर्माण कार्य के लिये मु० 10,000/- रु० का प्रावधान था तथा यह रुकम पंचायत प्रधान को विमुक्त (released) की गई है। पंचायत रिकार्ड के अनुसार उक्त कार्य पर मुबलिक 9711.50 खर्च किया गया है तथा कनिष्ठ अभियन्ता, विकास खण्ड जंजैहली द्वारा इस कार्य का मूल्यांकन मु० 10,000/- रु० किया गया है। इस कार्य का समाप्त प्रमाण-पत्र भी सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता जंजैहली तथा खण्ड विकास अधिकारी जंजैहली द्वारा जारी किया गया है। मगर सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर की रिपोर्ट अनुसार इस कार्य पर केवल मुबलिक 1000/- रुपये व्यय किया गया है। इस प्रकार आपने विकास खण्ड कार्यालय के कनिष्ठ अभियन्ता की मिलीभगत से मुबलिक 8,711.50 का छलहरण किया।

### 3. निर्माण झरान्डी से मझाखल तथा कन्डी सिचाई कूहल :

तकनीकी रिपोर्ट अनुसार झरान्डी से मझाखल तथा कन्डी सिचाई कूहल निर्माण कार्य नहीं किया गया है। जबकि इन दोनों कूहलों के निर्माण कार्यों के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र सतर्कता कमेट्री की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इस उद्देश्य के लिये क्रमशः मु० 50,000/-, 50,000/- रु० की धनराशि स्वोक्त की गई थी तथा सारी राशि विमुक्त (released) की गई है। मौके पर इन कूहलों के निर्माण का कोई भी सबूत व सामग्री नहीं पाई गई। पूछताछ करने पर प्रधान ने मौखिक तौर पर बताया कि कच्ची कूहलों का निर्माण किया गया है। लेकिन सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई भी कूहल का निर्माण नहीं किया गया था। पंचायत अभिलेख भी इन कार्यों पर व्यय किये गये क्रमशः मु० 44,646.75 तथा मु० 48,495/- रु० की पुष्टि करता है। मगर मौके पर कार्य न करके आपने उपरोक्त दोनों राशियों का स्पष्ट रूप से छलहरण किया है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि आपने प्रधान, ग्राम पंचायत तुंगाधार, विकास खण्ड मन्त्र, जिला मण्डी के पद पर रहते हुये गम्भीर विस्तीय अनियमिततायें करने के साथ-साथ रिकार्ड में हेरा-फेरी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में लापरवाही व अनदेखी की जिसके परिणामस्वरूप आप उपरोक्त वर्णित सरकारी धन व पंचायत निधि के छलहरण करने में सफल पायी गई। अतः आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से हटाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व आपको इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि आप स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहती है तो सचिव (पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार, जिमला-2 के समक्ष राज्य सचिवानय, आर्मजडेल स्थित जिमला-2 के कार्यालय में उपस्थित हो सकती है।

आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 (1) के अन्तर्गत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

अनुलग्नक जांच रिपोर्ट।

श्रीमती जस्ती देवी,  
प्रधान ग्राम पंचायत तुंगधार (निलम्बित),  
विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

शिमला-9, 15 सितम्बर, 2004

संख्या पी०सी० एच० एच० ए० (5) 13/94-13738-44.—यह कि उपायुक्त मण्डी द्वारा आपको प्रधान, ग्राम पंचायत बालीचौकी, विकास खण्ड सराज के पद से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग व अनियमितताओं में संलिप्त होने के आरोप से उनके कार्यालय आदेश संख्या पीसीएन-एमएनडी/2001-6382-88, दिनांक 1-11-2003 द्वारा निलम्बित किया गया था।

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु नियमित जांच हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मण्डी, जिला मण्डी को उपायुक्त, मण्डी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पीसीएन-एमएनडी/2001-6697-6704, दिनांक 25-11-2003 को सौंपी गई थी।

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाये गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त पाया गया कि :

आरोप संख्या 1 से 3. दिनांक 8-11-1993 को सहकारी बैंक से ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित किये बगैर एक अधिकार पत्र जारी कर मु० 10,000/- रु० की राशि को अपने व्यक्तिगत खाता संख्या-393 में परिवर्तित कर उक्त राशि का दुरुपयोग किया है। इसी प्रकार दिनांक 29-11-2003 को मु० 40,000/- रु० की राशि भी सहकारी बैंक बालीचौकी से निकाली गई। ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच पर पाया गया कि इस राशि की निकासी हेतु पंचायत का प्रस्ताव संख्या-4 पारित था परन्तु इस प्रस्ताव में मु० 60,000/- रु० की निकासी प्रस्तावित थी जबकि बैंक संख्या-30842 द्वारा मु० 40,000/- रु० की राशि की निकासी की गई है। पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में उक्त राशि की निकासी का अधिकार ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को दिया गया था परन्तु प्रधान (नि०) द्वारा उक्त राशि की निकासी स्वयं की गई और इस राशि का न ही रोकड़ में इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार दिनांक 4-1-1994 को मु० 10,000/- रु० ग्राम पंचायत बालीचौकी के बचत खाता संख्या-1701 से तथा दिनांक 18-5-1993 को मु० 18,000/- रु० बचत खाता संख्या-1781 से पंचायत का प्रस्ताव पारित किये बगैर निकासी कर पंचायत को इस राशि की निकासी का कोई उचित प्रमाण न देने तथा रोकड़ में कहीं भी दर्ज न होने से इस राशि का भी निरन्तर दुरुपयोग किया जाता रहा है। इस प्रकार कुल मु० 78,000/- रु० की राशि ग्राम पंचायत बालीचौकी के बचत खाता में से पंचायत प्रस्ताव पारित किये बगैर स्वेच्छा से निकासी कर उपरोक्त राशि के दुरुपयोग के दोषी पाये गये हैं।

आरोप संख्या-4.

दिनांक 31-7-1994 को मु० 6827.25/- रु० की राशि अग्रिम दर्शा कर दिनांक 25-11-2000 को पुनः रसीद संख्या-5771 के अन्तर्गत बैंक में जमा कर दिया गया। जबकि पंचायत अभिलेख की जांच पर दिनांक 31-7-1994 को यह राशि नकद जेष पायी गई। अतः आप द्वारा दिनांक 31-7-1994 से दिनांक 25-11-2000 तक मु० 6827.25 की राशि को अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर दुरुपयोग किया गया है।

- आरोप संख्या-5. दिनांक 24-2-1994 को मु० 5000/- रु० की राशि श्री केसर सिंह सुपुत्र श्री परमा नन्द को बिना किसी प्रयोजन के अदायगी करना भी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार सिद्ध पाया गया।
- आरोप संख्या-6. दिनांक 24-2-2000 को मारकण्डा गाँ-मिल (जिसके मालिक आप स्वयं हैं) के नाम मु० 5000/- रु० की राशि का बिल इमारती लकड़ी अपनी गाँ-मिल में जारी करके अदायगी दर्शाकर पंचायत में लाभ उठाने की चेष्टा की है।

आरोप संख्या-1 से 6 पर जांच अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट का सरकार द्वारा विचार करने के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि आप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (बी) के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से ठीकी पाये गये हैं।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप द्वारा बरती गई उपरोक्त वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिये क्यों न आपको प्रधान पद से निष्काशित किया जाये।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(2) के अन्तर्गत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मण्डी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

अनूलग्नक-जांच रिपोर्ट।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
सचिव।

श्री श्याम सिंह,  
प्रधान (नि०) ग्राम पंचायत बालीचौकी,  
विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

